

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

नं०	किस्म	ता०दायरा	तारीख निर्णय
/ 13	दावा	21.06.2013	21.03.2018

1. सुशीला बेवा सिट्टू। जातिगण मीना निवासी खिरखिड़ा तहसील सपोटरा
2. मनोज पुत्र सिट्टू। जिला करौली राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. रूमाल पुत्र चौथ्या। जातिगण मीना निवासी खिरखिड़ा तह० सपोटरा
2. रामसिंह पुत्र प्रभू। जिला करौली राजस्थान।
3. रामकेश पुत्र चौथ्या।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

प्रस्थित:- श्री राजाराम मीना एड० वकील वादीगण।

श्री कुंजबिहारी शर्मा एड० वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं० 49 रकबा 17 बिस्वा, ख०नं० 123 रकबा 15 बिस्वा, ख०नं० 243 रकबा 09 बिस्वा, ख०नं० 281 रकबा 06 बिस्वा कुल कित्ता 4 कुल रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खिरखिड़ा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी की आराजी है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 15.06.2013 को प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात को लट्ट के बल पर जोत कर कब्जा कर लिया है। वादीया बेवा औरत जात है इसका नाजायज फायदा उठाकर खातेदारी की आराजीयात को हड़पना चाहते है। वादीगण ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी खातेदारी की आराजीयात को आप लोगो ने क्यों जोता तो प्रतिवादीगण ने कहा कि इस आराजीयात को तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। तुम्हे इस जमीन मे घुसने नही देंगे। यदि तुम लोग जमीन जोतने आये तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे। प्रतिवादीगण लट्ट वाले पैसे वाले सहजोर व्यक्ति है, इसलिए वादीगण की खातेदारी पर कब्जा करके वादीगण को भूमिहीन करना चाहते है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को वेदखल किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं० 49 को सिट्टू पुत्र जगन्या ने अपने जीवनकाल मे ही रूपनारायण पुत्र किलाण्या मीना निवासी खिरखिड़ा को दिनांक 07.07.86 को स्टॉम्प कीमतन 5 रूपये पर तहरीर विक्रय पत्र लिखकर गवाहान के समक्ष कब्जा व स्वामित्व संभलवा दिया। इसके पश्चात् मुझ प्रतिवादी सं० 1 ने उक्त आराजी को 13 वर्ष पूर्व रूपनारायण को 28000/- रूपये उधार देकर रहन रख लिया तभी से उक्त विवादित भूमि पर मुझ प्रतिवादी सं० 1 का कब्जा व स्वामित्व है। खसरा नं० 123 को मुझ प्रतिवादी नं० 1 के पिता के जीवनकाल मे ही आज से लगभग पचासों वर्ष पूर्व सिट्टू पुत्र जेक्या पुत्र गेंदया से विनिमय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से आज दिनांक तक मुझ प्रतिवादी सं० 1 का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। वादीगण का उक्त आराजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नही है। आराजी खसरा नं० 243 रकबा 09 बिस्वा भूमि मुझ प्रतिवादी सं० 2 द्वारा जगन्या पुत्र गेंदया सिट्टू पुत्र जगन्या मीना निवासी खिरखिड़ा से रोकड़ी रूपया 11500/- मे कय कर दिनांक 22.06.1987 को कब्जा स्वामित्व संभाल लिया था। वादीगण का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का वास्ता नही है। आराजी खसरा नं० 281 रकबा 06 बिस्वा, जो कि कयशुदा भूमि है, पर भी मेरा कब्जा काशत है। खसरा नं० 281 की लिखा पढी भी सिट्टू पुत्र जगन्या द्वारा की गई है। वादीया चतुर चालाक किस्म की महिला है जिसका सिट्टू की उक्त विवादित आराजीयात से दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई वास्ता नही रहा है। सिट्टू ने अपने जीवनकाल मे किसी भी गल्लिया से विवाह नही किया है। सिट्टू लाओलाद फोट हुआ है। सिट्टू के साथ वादीया का दाम्पत्य रिश्ता नही था, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया सिट्टू की पत्नि होना साबित कर पायी है। वादीया स्थायी रूप से ग्राम खिरखिड़ा मे निवास नही कर रही है। वादीया उक्त आराजी मे अपने जीवनकाल मे कभी भी नही गई है तथा ना ही वादीया

ने उक्त आराजी पर कभी किसी प्रकार की काश्त की है। इसलिए दावा वादीया खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पांच तनकीयात कायम की गई। वकील वादीया ने साक्ष्य में वादीया सुशीला पीडब्ल्यू-1 का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वकील वादीया ने नकल जमाबंदी ग्राम खिरखिड़ा सम्बत् 2066-69 पेश की है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में प्रतिवादी सं० 1 रूमाल डीडब्ल्यू-1, प्रति० सं० 2 डीडब्ल्यू-2 रामसिंह एवं गवाह कैलाश के शपथ पत्र पेश किये हैं प्रतिवादी सं० 1 व 2 से जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल तहरीर वयनामा दिनांक 22.6.87, नकल तहरीर वयनामा दिनांक 07.7.86, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बालोती, वोटर लिस्ट किता 2, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रतियां पेश किये हैं।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:-

1. आया विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। भूमि का जमाबंदी सं० 2066-69 विवादित आराजी वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। अतः मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राईट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।
2. आया प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी पर कब्जा कर लिया है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे एवं साक्ष्य में स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं० 49 को सिट्टू पुत्र जगन्या ने अपने जीवनकाल में ही रूपनारायण पुत्र किलाण्या मीना निवासी खिरखिड़ा को दिनांक 7.7.86 को 5 रुपये के स्टॉम्प पर तहरीर लिखकर बेच दिया था तथा कब्जा केता को संभला दिया था, इसके पश्चात् प्रतिवादी नं० 1 ने 28000/- रुपये उधार देकर 13 वर्ष पूर्व उक्त खसरा नं० की भूमि को रूपनारायण से लेकर रहन रख लिया था तभी से उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 का कब्जा है।

पत्रावली के संलग्न तहरीर का अवलोकन किया गया। तहरीर में कहीं पर भी बेचान की गई भूमि का खसरा नं० अंकित नहीं है, पुनश्च 100 रुपये से अधिक की अचल सम्पत्ति का कोई भी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। 100 रुपये से अधिक की भूमि का अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रतिवादी नं० 1 ने 28000/- रुपये में रूपनारायण से भूमि रहन रखने का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उधार में पैसे देकर किसी भी खातेदार की भूमि को रहन रखना कानून सम्मत नहीं है, इसलिए विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं० 1 की उपरोक्त दलीले स्वीकार नहीं है तथा विवादित आराजी खसरा नं० 49 पर प्रतिवादीगण का कब्जा विधि विरुद्ध है।

प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जवाबदावे में अंकित किया है कि उसके पिता ने विवादित आराजी खसरा नं० 123 का विनिमय लगभग 50 वर्ष पूर्व सिट्टू पुत्र जगन्या से कर लिया था तथा तभी से आराजी विवादित प्रतिवादी के कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विनिमय का आदेश जारी करने की शक्ति तहसीलदार को है जिसका उल्लेख कहीं पर भी प्रतिवादी नं० 1 ने अपने जवाबदावे में नहीं किया है। इसलिए उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं० 1 की दलील स्वीकार योग्य नहीं है तथा विवादित आराजी खसरा नं० 123 पर कब्जा बनाये रखने का उनको कोई अधिकार नहीं है, अतः उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी नं० 1 का कब्जा काश्त विधि विरुद्ध है।


प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नं० 243 रकबा 09 बिस्वा प्रतिवादी नं० 2 ने जगन्या पुत्र गेंदया सिट्टू पुत्र जगन्या मीना निवासी खिरखिड़ा से 11500/- में दिनांक 22.06.87 को जरिये स्टॉम्प तहरीर कय की है तथा इसी प्रकार विवादित आराजी खसरा नं० 281 रकबा 06 बिस्वा भी प्रतिवादी नं० 2 की कय शुदा भूमि है तथा कय कि दिनांक से ही उसका कब्जा काश्त उक्त दोनो खसरा नम्बरान की विवादित भूमि पर है। पत्रावली में संलग्न तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें कहीं पर भी बेचान की गई भूमि का खसरा नं० अंकित नहीं है, पुनश्च 100/- से अधिक की अचल सम्पत्ति का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः विवादित आराजीयात खसरा नं० 243 व 281 के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं० 2 की दलीले स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा

बनाये रखने का प्रतिवादी नं० 2 को कोई अधिकार नहीं है, इसलिए विवादित आराजीयात खसरा नं० 243 व 281 पर प्रतिवादी नं० 2 का कब्जा काश्त विधि विरुद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के वादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 का कब्जा काश्त विधि विरुद्ध है, इसलिए वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए यह तनक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड वादीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। इसलिए वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि से दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. आया वादीया सिट्टू की विवाहित पत्नी नहीं है तथा वादीया ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सिट्टू की विरासत का झूठा नामान्तरकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में गलत नाम इन्द्राज करवाया है, इसलिए दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीया सिट्टू की विवाहित पत्नी है या नहीं, वादीया ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर विरासत का झूठा नामा० खुलवाया है अथवा नहीं आदि विषयों पर निर्णय घोषणात्मक वाद में किया जाना संभव होता है। उक्त वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 का है जिसमें उपरोक्त प्रश्नों पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। यदि राजस्व रिकार्ड में किसी भी खातेदार का नाम गलत तरीके से इन्द्राज किया गया हो तो प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद ला सकता है या नामान्तरकरण की अपील कर सकता है जिस पर सुनवाई के पश्चात् मैरिट पर निर्णय किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. आया आराजी खसरा नं० 49 प्रतिवादी सं० 1 के गत 13 वर्षों से रहन है, खसरा नं० 123 पर प्रतिवादी सं० 1 के पिता के जीवनकाल से ही पचासों वर्ष पूर्व से ही जरिये विनिमय कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा खसरा नं० 243, 281 को प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये तहरीर कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है इसलिए दावा वादीगण कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। उक्त दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। बेदखली का दावा तभी किया जा सकता है जबकि दावा करने वाले व्यक्ति का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो अर्थात् ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का है जिनको कब्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त वाद में प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा साबित है, वादीगण वाद पत्र में प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का अनुतोष चाहते हैं, इसलिए कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
6. अनुतोष:- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के वादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त विधि विरुद्ध है। अतः दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली